श्रीमान्त दत्ताजीराव

बहरोजीराव घोरपडे

बनाम

श्रीमान्त विजयसिंहराव और अन्य

(एस. के. दास, ए. के. सरकार और एम. हिदायतुल्ला, जे. जे.)

सरंजम एस्टेट-कनिष्ठ सदस्य को रख रखाव अनुदान,सरकार लाइनियल के कस्टम को फिर से शुरू करने और फिर से अनुदान देने के लिए ज्येष्ठाधिकार, सीमा और प्रभाव-सूट चुनौतीपूर्ण बहाली एवं पुनः अनुदान का सरकारी आदेश-यदि वर्जित है-सरंजम नियम-बॉम्बे राजस्व क्षेत्राधिकार अधिनियम, 1876 (बॉम्बे)1876 का एक्स), एस. 4.

धारक की मृत्यु पर, सरकार 7 जून, 1932 के आदेश द्वारा बम्बई ने सरंजाम फिर से शुरू कर दिया। गजेंद्रगढ़ की संपत्ति और अपने सबसे बड़े को फिर से दे दी। इसी आदेश से कुछ भूमियों का आवंटन किया गया। संपत्ति परिवार के एक छोटे सदस्य बी के पक्ष में, रखरखाव के माध्यम से भी कार्य जारी रखा गया। 14 मई 1940 को, बी अपनी विधवा ए और अपने अविभाजित भाई डी. ए को छोड़कर मर गया सरकार से बेटा गोद

लेने की इजाजत मांगी लेकिन अनुमति दिए बिना 10 जुलाई को वी अपनाया गया,1941. 17 दिसंबर, 1941 के एक आदेश द्वारा, सरकार डी को रखरखाव अनुदान (सरंजम पोटगी) जारी रखा। इसके बाद वी ने सरकार और डी के खिलाफ मुकदमा दायर किया।(i) आदेश के आधार पर भूमि की वसूली 17 दिसंबर, 1941 की सरकार की अधिसूचना अधिकारातीत थी, शून्य और शून्य, और (ii) वह वंशानुगत रीति से ज्येष्ठाधिकार जो परिवार में भूमि पर प्रचलित था बी की मृत्यु और ए द्वारा वी को गोद लेने पर, हस्तांतरित किया गया डी की प्राथमिकता में वी पर। मुकदमा लड़ा गया था, अंतर अन्य बातों के अलावा, इस आधार पर: (i) प्रासंगिक सरंजम के तहत नियमों के अनुसार बी का हित उसकी मृत्यु पर समाप्त हो गया और था ऐसा नहीं है कि दिनांकित आदेश के बावजूद वी को हस्तांतरित किया जा सके 17 दिसम्बर 1941, (ii) कथित पारिवारिक प्रथा ने ऐसा किया भरण-पोषण अनुदान पर लागू नहीं होता और (iii) यह मुकदमा था एस के तहत वर्जित 4 बॉम्बे राजस्व क्षेत्राधिकार अधिनियम के,1876:

माना गया कि वादी भूमि का हकदार नहीं था, या तो सरंजम नियमों के तहत या प्रथा के तहत; आगे कि मुक़दमे को बंबई राजस्व के $-4 से रोक दिया गया था।क्षेत्राधिकार अधिनियम, 1876.

रखरखाव अनुदान (पोटगी होल्डिंग) का हिस्सा था। सरंजम और सरंजम की घटनाओं से शासित था। कार्यकाल और प्रासंगिक सरंजम

नियमों द्वारा। सरंजम अनुदान की इच्छा और खुशी से प्रदान किए गए या रोके गए। संप्रभु शक्ति और अनुदान हमेशा अधीन थे। पुनः औरंभ द्वारा रुकावट और निरसन, अस्थायी या निरपेक्ष। बी की मृत्यु पर यह सरकार के लिए खुला था। अनुदान को फिर से शुरू करना और इसे डी को देना और यही है। 17 दिसम्बर, 1941 के आदेश द्वारा किया गया। मृतक की विधवा द्वारा वादी को गोद लिया जा सकता है। सरकार द्वारा पारित आदेश के क्रियान्वयन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

दौलतराव मालोजीराव बनाम प्रोवींस ऑफ बोम्बे (1946) 49 बॉम्ब, एल.और. 270, संदर्भित।

यहां तक की वंशानुगत वंशानुक्रम की प्रथा के तहत भी अनुरोध किया गया। वादी, डी इसके बाद संपत्ति पाने का हकदार था। बी की मृत्यु। यह दलील नहीं दी गई कि संपत्तियां एक बार भी ऐसी थीं। निहित संपत्ति को बाद में विधवा द्वारा गोद लेने के बाद वापस ले लिया गया। इसके अलावा न तो यह दलील दी गई और न ही यह साबित किया गया कि यह प्रथा है। को फिर से शुरू करने का सरकार का अधिकार छीन लिया।

रखरखाव अनुदान और उसके लिए नया अनुदान देना। बॉम्बे राजस्व क्षेत्राधिकार अधिनियम, 1876 का उप-खंड 4,"के संबंध में सिविल न्यायालयों के क्षेत्राधिकार पर रोक लगा दी गई है" दी गई भूमि से

संबंधित सरकार के विरुद्ध दावे या सरंजम के रूप में आयोजित"।

वादी ने इसका पता लगाने के लिए कहा 17 दिसम्बर, 1941 का आदेश अमान्य था और रद्द हो गया मुकदमे में संपत्तियों को प्रभावित न करें। जब तक ऑर्डर न निकले अपने तरीके से, वादी वसूली का दावा करने का हकदार नहीं था कब्जे का. दावा वह था जो इसके अंतर्गत आता था एस की शरारत 4 और मुकदमा वर्जित कर दिया गया।

सिविल अपीलीय, क्षेत्राधिकार: 1960 की सिविल अपील संख्या 37। 1949 की पहली अपील संख्या 492 में बॉम्बे हाई कोर्ट के 12 नवंबर 1952 के फैसले और डिक्री के खिलाफ अपील, जो 20 अप्रैल के फैसले और डिक्री से उत्पन्न हुई थी। , 1949, प्रथम श्रेणी उप-न्यायाधीश, धारवाड़, 1943 के विशेष सिविल सूट संख्या 16 में।

अपीलकर्ता की ओर से एसएन एंडली, जेबी दादाचंजी, रामेश्वर नाथ और पीएल वोहरा।

नौनीत लाल, प्रतिवादी नंबर 1 के लिए।

बी.और.एल. अयंगर और टीएम सेन, प्रतिवादी संख्या 2 के लिए।

29 अप्रैल 1960 न्यायालय का निर्णय एसके दास, जे. द्वारा दिया गया था।

यह निर्णय और बॉम्बे के उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र पर एक अपील है। उक्त उच्च न्यायालय की12 नवंबर, 1952 की डिक्री, जिसके द्वारा उसने 1943 के विशेष सिविल सूट संख्या 16 में, धारवाड़ में सिविल जज, प्रथम श्रेणी, दिनांक- 20 अप्रैल, 1949 के फैसले को पलट दिया।

भौतिक तथ्य ये हैं.धारवाड़ जिले के तालुक रॉन में गजेंद्रगढ़ एक सरंजम संपत्ति है जिसे गजेंद्रगढ़ सरंजम के नाम से जाना जाता है, जिसका सरकार द्वारा बनाए गए सरंजम सूची में नंबर 91 है।उस संपत्ति के भीतर डिंदुर गांव और उनाचगेरी का सर्वेक्षण क्षेत्र संख्या 302 है, जो संबंधित संपत्तियां हैं।एक भुजंगाराव दौलतराव घोरपड़े प्रासंगिक समय में सरनजम संपत्ति के धारक थे।1932 में सरंजाम को फिर से शुरू किया गया और राजनीतिक विभाग में बॉम्बे सरकार के संकल्प संख्या 8969 दिनांक 7 जून, 1932 द्वारा उक्त भुंजंगाराव को पुनः प्रदान किया गया।इस संकल्प में कहा गया:

> "गवर्नर इन काउंसिल को यह निर्देश देते हुए खुशी हो रही है कि गजेंद्रगढ़ सरंजम को औपचारिक रूप से फिर से शुरू किया जाना चाहिए और मृतक सरंजमदार दौलतराव भुजंगाराव घोरपड़े के सबसे बड़े बेटे भुजंगाराव दौलतराव घोरपड़े को फिर से प्रदान किया जाना चाहिए, और इसे

खातों में उनके एकमात्र नाम से दर्ज किया जाना चाहिए। अंतिम धारक की मृत्यु की तारीख से धारवाड़ के कलेक्टर का। कलेक्टर को सरंजमदार को सरंजम संपत्ति के उन गांवों पर कब्जा करने के लिए कदम उठाना चाहिए जो मृतक सरंजमदार के कब्जे में थे।

काउंसिल में गवर्नर दक्षिणी डिवीजन के आयुक्त से सहमत हैं कि भाउबंदों द्वारा पोटगी धारकों के रूप में रखे गए कार्यभार उन्हें वर्तमान की तरह जारी रखे जाने चाहिए।"

घोरपड़े परिवार की छोटी शाखाओं में से एक बाबासाहेब बहिरोजीराव घोरपड़े थे, जिन्हें आगे चलकर बाबासाहेब के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने डिंदुर के उपरोक्त गांव और उनाचगेरी के सर्वेक्षण क्षेत्र संख्या 302 को (पोटगी धारक के रूप में) रखरखाव के माध्यम से अपने पास रखा। उनका दत्तोजीराव नामक एक अविभाजित भाई था, जो मुकदमे में प्रतिवादी नंबर 2 था और हमारे समक्ष अपीलकर्ता है। इस फैसले में हम उसे अपीलकर्ता कहेंगे। बाबासाहेब की मृत्यु 14 मई, 1940 को हो गई। उनकी मृत्यु के बाद वे अपने पीछे अबायाबाई नाम की एक विधवा और अपीलकर्ता, अपने अविभाजित भाई को छोड़ गए। 10 जुलाई, 1941 को, अबायाबाई ने विजयसिंहराव को अपने मृत पति के बेटे के रूप में गोद लिया। विजयसिंह

वादी थे जो मुकदमा लेकर आए थेऔर अब हमारे सामने मुख्य प्रतिवादी हैं।यह सुविधाजनक होगा यदि हम उसे वादी-प्रतिवादी कहें, और यहां बताएं कि वह भुजौगाराव के छोटे भाई का स्वाभाविक पुत्र था, अपीलकर्ता से अलग एक और दत्ताजीराव था जिसका नाम भी यही है।बाबासाहेब की मृत्यु पर अबायाबाई ने एक लड़के को गोद लेने के लिए सरकार से मंजूरी मांगी;अपीलार्थी द्वारा इस आवेदन का विरोध किया गया।17 दिसंबर, 1941 को, बॉम्बे सरकार ने निम्नलिखित शर्तों में एक प्रस्ताव पारित किया:

> "1. सरकार को यह निर्देश देते हुए खुशी हो रही है कि ग्राम डिंदुर और उनाकबगेरी के सर्वेक्षण संख्या 302 की सरंजम पोटगी होल्डिंग, जो मृतकों को रखरखाव के लिए सौंपी गई थी पोटगीदार, श्री बाबासाहेब बहिरजीराव घोरपड़े को, गजेंद्रगढ़ सरंजम के पुनः अनुदान के समय, उनके अविभाजित भाई, श्री दत्ताजीराव बबीरोजीराव घोरपड़े को जारी रखा जाना चाहिए।
>
> 2. सरकार सरंजम नियमों के नियम 7 के तहत यह निर्देश देते हुए भी प्रसन्न है कि नए पोटगीदार, श्री दत्ताजीराव बहिरोजीराव गबोरपड़े को, मृतक पोटगीदार, श्री बाबासाहेब बहिरोजीराव घोरपड़े की विधवा, बाई अबाईबाई

को वार्षिक रखरखाव भत्ता देना चाहिए। रुपये का उसके जीवन के लिए 300।

3. ये आदेश 14 मई, 1940 से प्रभावी होने चाहिए, यानी, जिस तारीख को मृतक पोटगीदार, बाबासाहेब बहिरोजीराव घोरपड़े की मृत्यु हुई थी।

4. आयुक्त एसडी से अनुरोध किया जाना चाहिए कि वे इन आदेशों को दिवंगत पोटगीदार की विधवा बाई अबाइबाई को उनकी याचिकाओं के संदर्भ में और डिंडूर के रैयतों को उनकी याचिका, दिनांक 12 मई, 1941 के संदर्भ में सूचित करें। । आदेशों को गजेंद्रगढ़ के वर्तमान सरंजमदार को भी सूचित किया जाना चाहिए।"

8 फरवरी, 1943 को, वादी-प्रतिवादी ने प्रतिवादी नंबर 1 के रूप में बॉम्बे प्रांत, अपीलकर्ता को प्रतिवादी नंबर 2 और अबायाबाई के खिलाफ प्रतिवादी के रूप में मुकदमा दायर किया। नहीं। 3. मुकदमा बॉम्बे प्रांत (अब बॉम्बे राज्य द्वारा प्रतिस्थापित) और अपीलकर्ता द्वारा लड़ा गया था।अबायाबाई ने वादी-प्रतिवादी के मामले का समर्थन किया, लेकिन इस दौरान उनकी मृत्यु हो गई।मुकदमे की पेंडेंसी।

वादी-प्रतिवादी का दावा था कि उसके गोद लेने पर उसके मृत दत्तक पिता की संपत्ति अपीलकर्ता को वरीयता में वंशानुगत वंशानुक्रम के नियम के अनुसार हस्तांतरित हो गई।वादी-प्रतिवादी की मुख्य दलील वादी के पैराग्राफ 6 में कही गई थी, जो इस प्रकार है:

> " 6. प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा 1941 में पारित सरकारी प्रस्ताव निम्नलिखित कारणों से अधिकारातीत और अमान्य है:
>
> (ए) प्रतिवादी नंबर 1 ने 1932 में श्रीमंत सरदार भुजरागाराव घोरपड़े को सरंजम संपत्ति का पुन: अनुदान दिया और प्रतिवादी नंबर 1 के अनुसार, मुकदमे की संपत्तियां वादी के दत्तक पिता को जारी रहीं, सरंजम नियमों के तहत कोई अवसर नहीं इस स्तर पर सरकार के हस्तक्षेप का मामला सामने आया है।सरकार द्वारा दिया गया पुनर्अनुदान किसी भी स्थिति में अनुदान प्राप्तकर्ता, श्रीमंत सरदार भुजंगाराव घोरपड़े के जीवन काल के दौरान प्रभावी होगा।इसके अलावा उक्त सरकारी प्रस्ताव से पहले प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा उक्त श्रीमंत सरदार भुजंगाराव घोरपड़े से परामर्श नहीं किया गया था।

(बी) जिस परिवार से वह संबंधित है, उसके रिवाज के अनुसार, मृत व्यक्ति की संपत्ति वंशानुगत वंशानुक्रम के नियम द्वारा हस्तांतरित होती है।इसलिए वादी के दत्तक पिता की मृत्यु और स्वयं वादी के गोद लेने के बाद, वादी के दत्तक पिता में निहित सारी संपत्ति प्रतिवादी नंबर 2 की तुलना में वादी को हस्तांतरित हो गई है। प्रचलित उत्तराधिकार के इस नियम की अनदेखी करने में प्रतिवादी नंबर 1 की कार्रवाई परिवार में अधिकार से बाहर और अशक्तता है।"

उपरोक्त दलीलों पर वादी-प्रतिवादी ने प्रार्थना कि (ए) अपीलकर्ता से मुकदमे में संपत्तियों के कब्जे की वसूली, (बी) मेस्ने मुनाफा, और (सी) लागत।बंबई प्रांत की ओर से बचाव के माध्यम से कई दलीलें दी गईं।मुख्य दलीलें थीं (1) यह मानते हुए कि वादी-प्रतिवादी को वैध रूप से गोद लिया गया था, फिर भी उसके पास मुकदमे में संपत्तियों पर कोई कानूनी दावा नहीं था क्योंकि प्रासंगिक सरंजम नियमों के तहत बाबासाबेब का हित उनकी मृत्यु पर समाप्त हो गया था और ऐसा नहीं था 17 दिसंबर, 1941 के सरकारी संकल्प के बावजूद वादी-प्रतिवादी को हस्तांतरित होनेवाली प्रकृति, (2) कि कथित पारिवारिक प्रथा रखरखाव अनुदान पर लागू नहीं होती है, और (3) कि, किसी भी घटना में, मुकदमे को इसके

तहत रोक दिया गया था एस।बॉम्बे राजस्व क्षेत्राधिकार अधिनियम, 1876 के 4। अपीलकर्ता ने उपरोक्त दलीलों का समर्थन करने के अलावा अतिरिक्त दलीलें दीं कि वादी-प्रतिवादी का कोई वैध गोद लेने का अधिकार नहीं था और अबायाबाई को उसके पति द्वारा बेटे को गोद लेने से स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया था।

इन दलीलों पर कई मुद्दे तय किए गए।मुकदमा मूल रूप से प्रारंभिक आधार पर खारिज कर दिया गया था, अर्थात्, वादी ने कार्रवाई के किसी भी कारण का खुलासा नहीं किया था।विद्वान सिविल न्यायाधीश ने स्पष्ट रूप से यह विचार किया कि मुकदमे में संपत्तियां सरंजम नियमों के अधीन थीं और उन नियमों की जांच करने पर, वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वादी-प्रतिवादी अपने गोद लेने पर अपीलकर्ता का भतीजा बन गया और इस अर्थ में वह था बाद वाले से भरण-पोषण का दावा करते हुए, उसके लिए उन आवश्यक परिस्थितियों का औरोप लगाना आवश्यक था जिसके तहत सरंजम परिवार के कुछ सदस्य उक्त नियमों के नियम 7 के तहत भरण-पोषण का दावा करने के हकदार हैं और चूंकि उन परिस्थितियों का वादी-प्रतिवादी द्वारा अनुरोध नहीं किया गया था, वादी ने कार्रवाई का कोई कारण नहीं बताया।उच्च न्यायालय ने ठीक ही बताया कि वादी-प्रतिवादी ने सरंजम नियमों के नियम 7 के तहत भरण-पोषण का दावा नहीं किया, बल्कि दावा किया कि मुकदमे में संपत्ति उसके गोद लेने और वंशानुगत

वंशानुक्रम की प्रथा के कारण उसे हस्तांतरित हो गई।इसलिए, उच्च न्यायालय ने माना कि वादी-प्रतिवादी का दावा केवल भरण-पोषण के दावे से कहीं अधिक मौलिक था, और विद्वान सिविल जज ने मुकदमे के वास्तविक दायरे के बारे में खुद को गलत बताया था।तदनुसार, उच्च न्यायालय ने बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया और सभी मुद्दों पर मुकदमा चलाने का निर्देश दिया।

इस निर्देश के बाद विद्वान सिविल जज ने सभी मामलों का विचारण किया. मुद्दे 1 और 2 गोद लेने के प्रश्न से संबंधित हैं, अर्थात्, (1) क्या गोद लेने का संस्कार उचित रूप से सिद्ध किया गया था और (2) क्या बाबासाहेब ने अपने जीवनकाल के दौरान अपनी पत्नी को गोद लेने से रोक दिया था।पहले मामले में विद्वान सिविल जज ने वादी-प्रतिवादी के पक्ष में फैसला सुनाया और दूसरे में उसके खिलाफ।उच्च न्यायालय ने पहले मुद्दे पर निष्कर्ष की पुष्टि की, और दूसरे मुद्दे पर रखे गए सबूतों की सावधानीपूर्वक और विस्तृत जांच पर कि विद्वान सिविल जज ने यह मानना गलत था कि बाबासाहेब के कथित निषेध के कारण गोद लेना अमान्य था।उच्च न्यायालय ने माना कि ऐसी कोई रोक नहीं थी और गोद लेना वैध था।हमें नहीं लगता कि उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष पर हमारे सामने सफलतापूर्वक हमला किया गया है या किया जा सकता है।इसलिए,

हम इस अपील में इस आधार पर आगे बढ़े हैं कि वादी प्रतिवादी को 10 जुलाई, 1941 को अबायाबाई द्वारा वैध रूप से गोद लिया गया था।

अब हम उन मुद्दों पर विचार करते हैं जो इस अपील के निर्णय के लिए महत्वपूर्ण हैं।वे हैं:

मुद्दा संख्या 3-क्या वादी मुकदमे की संपत्ति पर अपना हक साबित करता है?

मुद्दा संख्या 4-क्या यह साबित हो गया है कि 17 दिसंबर 1941 का सरकारी संकल्प (डीजी) संख्या 8969 अधिकारातीत और अमान्य है जैसाकि वादपत्र में औरोप लगाया गया है?

मुद्दा क्रमांक 5-क्या मुकदमा राजस्व क्षेत्राधिकार अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत वर्जित है?

मुद्दा क्रमांक 7-क्या कथित प्रथा पैरा में स्थापित है।वादपत्र का 6(बी) सिद्ध हुआ ?

इन सभी मुद्दों पर विद्वान सिविल जज ने वादी-प्रतिवादी के खिलाफ पाया, और माना कि वादी मुकदमे में संपत्तियों पर कब्ज़ा पाने का हकदार नहीं था, कि वह वादी के पैराग्राफ 6 (बी) में बताए गए रिवाज को साबित करने में विफल रहा था। , कि दिसंबर 17,1941 का सरकारी प्रस्ताव अधिकारातीत नहीं था, और यह मुकदमा स्वयं धारा के तहत वर्जित

था।बॉम्बे राजस्व क्षेत्राधिकार अधिनियम, 1876 के 4। उच्च न्यायालय ने उपरोक्त सभी मुद्दों पर विद्वान सिविल न्यायाधीश के फैसले को उलट दिया, और माना कि मुकदमे में संपत्तियाँ बाबासाहेब की कनिष्ठ शाखा को उसके रखरखाव के लिए दी गई थीं और वे अयोग्य थीं और वंशानुगत वंशानुक्रम के नियम द्वारा शासित, वे बाबासाहेब की मृत्यु के बाद अपीलकर्ता को हस्तांतरित हो गए;लेकिन जैसे ही बाबा साहेब की विधवावैध गोद लेने के बाद, संपत्तियों का विनिवेश कर दिया गया और चूंकि वादी-प्रतिवादी बाबासाहेब के परिवार की वरिष्ठ शाखा का सबसे बड़ा सदस्य बन गया, पारिवारिक रीति-रिवाज और सामान्य हिंदू कानून के संयुक्त प्रभाव के परिणामस्वरूप वह इसका हकदार बन गया।उच्च न्यायालय ने कहा कि इस दृष्टिकोण से देखने पर, 17 दिसंबर, 1941 के सरकारी प्रस्ताव की वैधता पर कोई सवाल नहीं उठता है, और सरकार के खिलाफ दावा किए जाने पर कब्जे के लिए कोई राहत नहीं है, मुकदमे को एस के तहत रोका नहीं गया था।बॉम्बे राजस्व क्षेत्राधिकार अधिनियम, 1876 के 4। अपीलकर्ता की ओर से, यह बहुत दृढ़ता से तर्क दिया गया है कि उच्च न्यायालय ने यह मानने में गलती की थी कि मुकदमे में संपत्तियां जो सरंजाम का हिस्सा हैं, अपीलकर्ता में निहित हैं। बाबा साहब की मृत्यु और फिर वादी-प्रतिवादी के गोद लेने पर उन्हें विनिवेशित कर दिया गया;यह तर्क दिया गया है कि इस तरह का निष्कर्ष सरंजम कार्यकाल की प्रकृति के साथ असंगत है और इसके अलावा, 17 दिसंबर,

1941 को पुनर्अनुदान के कारण अपीलकर्ता में निहित संपत्तियों को गोद लेने के द्वारा विनिवेश नहीं किया जा सकता है। 10 जुलाई, 1941 को। न ही यह दावा किया गया है, यह वादी के पैराग्राफ 6 (बी) में दी गई प्रथा का पालन करता है, सिवाय इस सवाल के कि क्या वह प्रथा साबित हुई है या नहीं, कि मुकदमे में संपत्तियां एक बार थीं वैध दत्तक ग्रहण पर अपीलकर्ता में निहित संपत्ति का विनिवेश किया जाएगा।दूसरे, यह तर्क दिया गया है कि उच्च न्यायालय ने भी यह मानने में गलती की थी कि चौथे उप-खंड के अर्थ में सरकार के खिलाफ कोई दावा नहीं था।का.बॉम्बे राजस्व क्षेत्राधिकार अधिनियम, 1876 का 4(ए)।

हमारे सामने तर्क यह रहा है कि ऐसा कोई दावा था, और किसी भी सिविल न्यायालय के पास इसे निर्धारित करने का अधिकार क्षेत्र नहीं था।हम संतुष्ट हैं कि ये तर्क सही हैं और इन्हें स्वीकार किया जाना चाहिए.वादी प्रतिवादी का दावा है कि उसके गोद लेने पर मुकदमे में संपत्तियां उसे हस्तांतरित कर दी गईं, इसकी जांच या तो सरंजम नियमों या उस प्रथा के दृष्टिकोण से की जा सकती है, जिसके बारे में उसने वाद के पैराग्राफ 6 (बी) में वकालत की थी।आइए पहले सरेनियम नियमों के दृष्टिकोण से दावे की जांच करें, यह मानते हुए कि वे यहां लागू होते हैं,जहां तक संभव हो, सरंजम के भीतर रखरखाव अनुदान (पोटगिस) के लिए।7 जून, 1932 के संकल्प में, जो पहले उद्धृत किया गया था, बंबई

सरकार ने पोटगी धारकों को सरनजम के भीतर माना और उनके लिए प्रावधान किया।17 दिसम्बर, 1941 का प्रस्ताव भी उसी आधार पर आगे बढ़ा।पहले के दो संकल्पों, एक 1891 (उदा. 100) और दूसरा 1936 (उदा. 101) में, पूरे गजेंद्रगढ़ और उसके कुछ हिस्सों को सरंजाम के रूप में माना गया।बाबासाहब अपने जीवन काल में सरंजमदार को अपने पक्ष में अनुदान समर्पित करना चाहते थे, लेकिन सरकार ने इस तरह के त्याग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।यहां तक कि अबायाबाई ने एक लड़के को गोद लेने के लिए सरकार से अनुमति मांगी, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं मिली।यह सब दर्शाता है कि पोटगी होल्डिंग सरंजाम का हिस्सा थी और सभी संबंधित पक्षों द्वारा उसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया गया था।

सरंजम क्या है?सरंजम शब्द का शाब्दिक अर्थ उपकरण, प्रावधान या सामग्री है। अपनी शब्दावली में, विल्सन ने सरंजम को सैनिकों के समर्थन के लिए या आमतौर पर अनुदान प्राप्तकर्ताओं के जीवनकाल के लिए व्यक्तिगत सेवा के लिए गांवों या भूमि से राजस्व के अस्थायी असाइनमेंट के रूप में परिभाषित किया है। डॉ. जीडी पटेल ने अपने लेख में "द इंडियन लैंड प्रॉब्लम एंड लेजिस्लेशन" नामक पुस्तक में कहा गया है:

सरंजम सूची की प्रस्तावना में कर्नल एथरिज द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार, राजस्व के अस्थायी असाइनमेंट द्वारा राज्य के उद्देश्यों

के लिए सामंती अभिजात वर्ग की एक प्रजाति को बनाए रखना पूर्व

सरकारों, दोनों मुसलमानों और मराठों की प्रथा थी। या तो सैनिकों के समर्थन के लिए या व्यक्तिगत सेवा के लिए, आधिकारिक गरिमा के रखरखाव के लिए या अन्य विशिष्ट कारणों के लिए। ऐसी भूमि के धारकों को उस समय राजस्व एकत्र करने और उचित करने और सामान्य प्रशासन करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्तियां सौंपी गईं थीं। भूमि का प्रबंधन। मुस्लिम शासन के तहत, ऐसी जोतों को जहांगीर कहा जाता था और मराठा शासन के तहत, उन्हें सरंजम कहा जाने लगा। हालांकि, मराठा काल के दौरान इन कार्यकालों के बीच यह अंतर समाप्त हो गया। ब्रिटिश शासन के दौरान,जहांगीर और सरंजम के बीच का अंतर सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए समाप्त हो गया। दोनों शब्द परिवर्तनीय हो गए और ऐसे सभी अनुदानों को सामान्य शब्द "सरंजम" से जाना जाने लगा।सरंजम अनुदानों के अलावा, जो केवल दक्कन में पाए जाते थे, राजनीतिक प्रकृति के अन्य अनुदान भी थे जो पूरे राज्य में बिखरे हुए पाए गए थे।उनकी उत्पत्ति सारंजम से भौतिक रूप से भिन्न नहीं थी, जिसके परिणामस्वरूप अंग्रेजों ने उनके साथ उन्हीं नियमों के तहत व्यवहार किया, जिन्हें सरंजम नियम कहा जाता था।

सरंजम नियम अधिनियम की अनुसूची बी के और. 10 में संदर्भित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए थे। 1852 के शी और 1863 के

बॉम्बे एक्ट VII की धारा 2 के दूसरे उप-सीएल से लेकर 3 तक। हम यहां इन नियमों में से कुछ को पुन: पेश कर सकते हैं:

"नियम I-सरंजाम को आमतौर पर पहले से ही लिए गए निर्णय के अनुसार जारी रखा जाएगा। पारित किया गया या जो इसके बाद प्रत्येक मामले में प्रांतीय सरकार द्वारा पारित किया जा सकता है।

नियम 2-ए सरंजम जिसे वंशानुगत रूप से जारी रखने का निर्णय लिया गया है, वह आम तौर पर ज्येष्ठाधिकार के क्रम में सबसे बड़े पुरुष प्रतिनिधि, परिवार की वरिष्ठ शाखा के प्रथम ब्रिटिश अनुदान प्राप्तकर्ता या उसके किसी भाई के वंशज होंगे जो हित में अविभाजित थे .लेकिन प्रांतीय सरकार पर्याप्त कारणों से उक्त परिवार के किसी अन्य सदस्य को या प्रांतीय सरकार की मंजूरी से उसी परिवार में गोद लिए गए किसी व्यक्ति को अनुग्रह के रूप में जारी रखने का निर्देश देने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है।जब एक सरंजम इस प्रकार एक दत्तक पुत्र को जारी रखा जाता है, तो वह प्रांतीय सरकार को सरंजम के एक वर्ष के मूल्य से अधिक नहीं का नज़राना देने के लिए उत्तरदायी होगा, और यह उससे ऐसी किश्तों में वसूला जाएगा जैसा कि प्रांतीय सरकार प्रत्येक मामले में निर्देश दे सकती है।

नियम 5- प्रत्येक सरंजाम को जीवन संपदा के रूप में रखा जाएगा।इसे धारक की मृत्यु पर औपचारिक रूप से फिर से शुरू किया

जाएगा, और जिन मामलों में यह आगे जारी रखने में सक्षम है, इसे प्रांतीय सरकार से नए अनुदान के रूप में अगले धारक को सौंप दिया जाएगा, सिवाय इसके कि किसी भी ऋण या शुल्क से मुक्त हो। जैसा कि विशेष रूप से प्रांतीय सरकार द्वारा ही लगाया जा सकता है।

नियम 7-प्रत्येक सरंजमदार अपने पूर्ववर्ती सरंजमदार, अपने भाइयों, या अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य की विधवाओं या विधवाओं के भरण-पोषण के लिए उपयुक्त प्रावधान करने के लिए जिम्मेदार होगा, जिनके पास कोई संपत्ति नहीं है। शैशवावस्था, मानसिक या शारीरिक विकृति से उत्पन्न वैध दावा, जिससे ऐसा सदस्य आजीविका कमाने में असमर्थ हो जाता है, को उसके हाथों समर्थन के योग्य माना जा सकता है।जब यह दायित्व किसी सरंजमदार द्वारा पूरा नहीं किया जाता है, तो प्रांतीय सरकार उसे ऐसे व्यक्ति के लिए उपयुक्त प्रावधान करने का निर्देश दे सकती है और राशि तय कर सकती है, जिसे वह प्रत्येक उदाहरण में भुगतान करेगा;बशर्ते कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास अपना स्वतंत्र साधन है, या प्रांतीय सरकार की राय में, अन्यथा पर्याप्त रूप से प्रदान किया गया है, सरंजमदार से भरण-पोषण का हकदार नहीं होगा।

नियम 8-सरंजमदार द्वारा गुजारा भत्ता देने के लिए उपरोक्त नियम के तहत प्रांतीय सरकार द्वारा पारित प्रत्येक आदेश केवल उसके जीवन के दौरान ही मान्य होगा।

सरंजम कार्यकाल की वास्तविक प्रकृति पर बंबई उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने दौलतराव मालोजीराव में विचार किया था। बंबई प्रांत (1) जहां शेख सुल्तान सानी बनाम शेख अजमोदीन (2) और राघोजीराव बनाम लक्ष्मणराव (3) में पहले के फैसलों का जिक्र करने के बाद उनका आधिपत्य देखा गया:

"अधिकारियों की एक परीक्षा से यह स्पष्ट हो जाता है कि सरंजम कार्यकाल की पूरी संरचना संप्रभु अधिकार पर आधारित है, जो केवल विजय या संधि द्वारा बदल सकती है। इस प्रकार स्थापित, जागीर और सरंजम, उनके साथ जुड़ी सामंती घटनाओं के साथ, संप्रभु की इच्छा और खुशी पर दी या रोकी जाती हैं शक्ति, और, यदि प्रदान की जाती है, तो कार्यकाल की निश्चितता हमेशा रुकावट और बहाली द्वारा निरस्तीकरण के अधीन होती है, चाहे वह अस्थायी हो या प्रकृति में पूर्ण। कोई भी घटना सामान्य रूप से लागू नहीं होती है। (1) (1946) 49 बॉम। एलऔर 270।

(2) (1892)) एलऔर 20 आईए 50. (3) (1912) 14 बम।एलऔर 1226.

विषय और विषय के बीच निजी अधिकार संप्रभु इच्छा को बाधित या परेशान कर सकते हैं।

हमें यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट प्रतीत होता है कि सरंजम नियम वादी प्रतिवादी के दावे के लिए कोई आधार नहीं देते हैं।अबायाबाई ने एक लड़के

को गोद लेने की मंजूरी मांगी।ऐसी कोई मंजूरी नहीं दी गई.बाबासाहेब की मृत्यु पर, अनुदान को फिर से शुरू करना सरकार के लिए खुला था, और 17 दिसंबर, 1941 के अपने संकल्प द्वारा, सरकार ने निर्देश दिया कि डिंडूर गांव और उनाचगेरी के सर्वेक्षण संख्या 302 की सरंजम पोटगी जोत अपीलकर्ता को जारी रखी जानी चाहिए।यह वास्तव में एक बहाली और नए अनुदान के बराबर है और हम उच्च न्यायालय से सहमत नहीं हैं कि पारित आदेश उत्तराधिकार के नियम के अनुसार कानूनी स्थिति को पहचानने से ज्यादा कुछ नहीं है और सामान्य उत्परिवर्तन के किसी भी आदेश के समान स्तर पर है।उच्च न्यायालय ने 17 दिसंबर, 1941 के संकल्प में "जारी रखें" शब्द के उपयोग पर जोर दिया है, और उस संकल्प की तुलना 7 जून, 1932 के पहले के संकल्प से की है, जो स्पष्ट रूप से पुनः औरंभ और पुनर्ग्रहण को प्रभावी करने वाला एक संकल्प था। गजेंद्रगढ़ सारंजम.हालाँकि, यह बताया जा सकता है कि पिछले संकल्प के पैराग्राफ 2 में, सरकार ने रखरखाव अनुदान, अर्थात् सरंजम के भीतर पोटगी होल्डिंग्स के संबंध में एक ही शब्द "जारी" का उपयोग किया था।इसलिए, "जारी" शब्द के उपयोग पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है और यदि 17 दिसंबर, 1941 के संकल्प को समग्र रूप से पढ़ा जाए, तो यह स्पष्ट है कि ग्राम डिंडूर की पोटगी और उनाचगेरी के सर्वेक्षण क्षेत्र संख्या 302 को प्रदान किया गया था। वर्तमान अपीलकर्ता.ऐसा आदेश पारित करना सरकार के लिए खुला था, और हमें यह मानने का कोई कारण नहीं

दिखता कि यह अमान्य था।वास्तव में, उच्च न्यायालय ने यह नहीं कहा कि यह एक अमान्य आदेश था;इसके विपरीत, इसने कहा कि यह एक अच्छा आदेश था और बाबासाहेब की मृत्यु के प्रभाव से संचालित हुआ।लेकिन हमारी राय में यह गलती से कहा गया कि गोद लेने की बाद की घटना के कारण, सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, आदेश का उस घटना से कोई प्रभाव नहीं पड़ा।यह अच्छी तरह से याद रखना चाहिए कि गोद लेने की प्रक्रिया 10 जुलाई, 1941 को हुई थी और प्रस्ताव 17 दिसंबर,1941 को पारित किया गया था, हालांकि यह बाबासाहेब की मृत्यु की तारीख से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू हुआ था।हमें कोई कारण नहीं दिखता कि एस, सरकार द्वारा दिया गया एक वैध आदेश सरकार की मंजूरी के बिना अबायाबाई द्वारा अपनाए गए गोद लेने के कारण कोई प्रभाव नहीं डालेगा।यह मानना कि किसी निजी पार्टी के कृत्य के कारण सरकारी आदेश का कोई प्रभाव नहीं रह गया है, सरंजम कार्यकाल की प्रकृति के विरुद्ध जाना होगा।

आइए अब हम वादी प्रतिवादी के दावे की जांच वादी के पैराग्राफ 6(बी) में बताए गए कस्टम के दृष्टिकोण से करें।प्रचलित प्रथा वंशानुगत वंशानुक्रम का नियम थी।सरकार ने अपने लिखित बयान में कहा:

"खंड (बी) में कथित पारिवारिक प्रथा को स्वीकार नहीं किया गया है, और इस बात से इनकार किया गया है

कि ऐसी प्रथा भरण-पोषण अनुदान के संबंध में लागू हो सकती है। सरंजम नियमों के नियम 7 के तहत, जो केवल सरंजम से संबंधित प्रथागत कानून को शामिल करता है, सरकार है आदेश देना है या नहीं, क्या प्रावधान करना है और किसके पक्ष में करना है, यह निर्धारित करने का पूर्ण विवेक दिया गया है।"

अपीलकर्ता ने कहा:

"वादी के पैराग्राफ 6 (बी) की सामग्री सही नहीं है। ज्येष्ठाधिकार के नियम द्वारा वंश की प्रथा से इनकार किया जाता है। यह प्रतिवादी बाबासाहेब की मृत्यु के बाद जीवित रहकर मालिक बन गया है।"

विद्वान सिविल जज ने पाया कि वादपत्र के पैराग्राफ 6(बी) में बताई गई प्रथा सिद्ध नहीं हुई है।उच्च न्यायालय ने ऐसे किसी साक्ष्य का उल्लेख नहीं किया है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि यह प्रथा साबित हुई है, लेकिन यह कहा कि "यह सामान्य आधार है कि जो संपत्तियां इस शाखा को इसके रखरखाव के लिए सौंपी गई थीं, वे निष्पक्ष हैं और वंशानुक्रम के आधार पर चलती हैं"।भले ही हम यह मान लें कि उच्च न्यायालय अपनी टिप्पणी में सही है, हालांकि दो लिखित बयानों में इनकार के सामने यह देखना मुश्किल है कि यह पार्टियों के बीच सामान्य आधार

कैसे हो सकता है, हम यह समझने में विफल हैं कि यह धारणा वादी को कैसे मदद करती है - प्रतिवादी. बाबा साहब की मृत्यु के बाद वंशानुगत वंशानुक्रम का नियम लागू होने पर अपीलकर्ता संपत्तियों का हकदार हो गया और उसे मिल गया। वादपत्र में यह दलील नहीं दी गई थी कि एक बार वंशानुगत वंशानुक्रम के प्रथागत नियम के तहत निहित संपत्तियों को विधवा द्वारा बाद में गोद लेने पर वापस ले लिया गया था। ऐसी कोई याचिका विशेष रूप से नहीं ली गई थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा दी गई रियायत पर भरोसा किया कि सामान्य हिंदू कानून के तहत जो संपत्तियां अपीलकर्ता में निहित थीं, उन्हें विधवा द्वारा बाद में वैध गोद लेने पर विनिवेशित कर दिया गया था। हम विधवा द्वारा बाद में वैध गोद लेने पर संपत्ति के विनिवेश के जटिल प्रश्न पर विचार करना अनावश्यक मानते हैं। यह इंगित करने के लिए पर्याप्त है कि वादी ने ऐसे किसी मामले का खुलासा नहीं किया; ऐसा कोई मुद्दा नहीं उठाया गया था और वादी-प्रतिवादी के लिए अपील में पहली बार कोई नया मामला बनाना खुला नहीं था। वादी-प्रतिवादी ने वंशानुक्रम के सामान्य कानून से भिन्न वंशानुगत वंशानुक्रम की एक पारिवारिक प्रथा स्थापित की; यह उस पर निर्भर था कि वह उस प्रथा पर औरोप लगाए और उसे साबित करे जिस पर वह भरोसा करता था और उसकी सटीक सीमा को दिखाए और यह सामान्य हिंदू कानून पर कितनी प्रबल थी। हमारी राय में, वह किसी भी पारिवारिक रीति-रिवाज की पैरवी करने या उसे साबित करने

में विफल रहा, जिसके तहत संपत्तियां उसे हस्तांतरित हुईं।इसके अलावा, सफल होने के लिए वादी प्रतिवादी को यह भी स्थापित करना होगा कि प्रथा ऐसी थी जो सरकार को बाध्य करेगी।अपीलकर्ता और सरकार ने कभी यह स्वीकार नहीं किया कि वंशानुगत वंशानुक्रम की प्रथा, यदि यह परिवार में प्रचलित है, तो सरकार के भरण-पोषण अनुदान को फिर से शुरू करने का अधिकार छीन लेती है, जो सरंजम का हिस्सा था और सरंजम नियमों के अनुसार नया अनुदान देता है।

अब, जहाँ तक एस.बॉम्बे राजस्व क्षेत्राधिकार अधिनियम, 1876 की धारा 4। यह धारा, जहां तक यह हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है, कहती है:-

"एस. 4.-इसके बाद आने वाले अपवादों के अधीन, कोई भी सिविल न्यायालय निम्नलिखित में से किसी भी मामले पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करेगा:

(ए) बॉम्बे अधिनियम संख्या के तहत नियुक्त या मान्यता प्राप्त किसी वंशानुगत अधिकारी के कार्यालय से संबंधित किसी भी संपत्ति से संबंधित सरकार के खिलाफ दावा।1874 का III या तत्समय लागू कोई अन्य कानून, या किसी अन्य ग्राम-अधिकारी या सेवक का, या ऐसे किसी अधिकारी या सेवक के कर्तव्यों का पालन करने का दावा, या किसी चोट के संबंध में, ऐसे बहिष्कार से कार्यालय या सेवा, या राज्य सरकार या उस संबंध में

विधिवत अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा पारित उसी अधिनियम या उसी विषय से संबंधित किसी अन्य कानून के तहत किसी भी आदेश को रद्द करने या टालने के लिए मुकदमा, या उसके खिलाफ दावा संधि के तहत धारित भूमि से संबंधित सरकार, या सरंजम के रूप में दी गई या धारित भूमि से संबंधित, या अन्य राजनीतिक स्वामित्व पर, या प्रांतीय सरकार या सेवा के लिए रखे जाने के लिए उस संबंध में विधिवत अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा घोषित भूमि से संबंधित।

मल्लप्पा उर्फ अन्नासाहेब बसवंतराव देसाई नादगौड़ा बनाम तुक्को नरसिम्हा मुतालिक देसाई और अन्य(1) में यह बताया गया था कि अनुभाग में दावों और मुकदमों के बीच अंतर किया गया है।जिस उपधारा से हम चिंतित हैं वह चौथा उपधारा है जो अन्य बातों के साथ-साथ "सरंजाम के रूप में दी गई या धारित भूमि से संबंधित सरकार के खिलाफ दावों" से संबंधित है।उच्च न्यायालय का मानना है कि वर्तमान मामले में सरकार के खिलाफ कोई दावा नहीं किया गया है।हम सहमत नहीं हो पा रहे हैं.स्पष्ट शब्दों में, वादी प्रतिवादी ने यह निष्कर्ष निकालने के लिए कहा कि 17 दिसंबर, 1941 का सरकारी संकल्प शून्य और शून्य था और मुकदमे में संपत्तियों को प्रभावित नहीं करता था क्योंकि सरकार के पास ऐसा आदेश देने का कोई अधिकार नहीं था या ऐसा करने का कोई अवसर नहीं था। इसलिए।उन्होंने सरकार के आदेशों के बावजूद उन संपत्तियों पर

कब्ज़ा मांगा।इन परिस्थितियों में हमें यह मानना चाहिए कि सरकार एक विशुद्ध रूप से औपचारिक पार्टी से अधिक थी, और 17 दिसंबर, 1941 के संकल्प में निहित आदेशों के संबंध में इसके खिलाफ दावा किया गया था। जब तक संकल्प उसके रास्ते से बाहर नहीं हो जाता, वादी- प्रतिवादी अपीलकर्ता से मामूली लाभ आदि के साथ कब्जे की वसूली का दावा करने का हकदार नहीं है। सरंजम भूमि से संबंधित 17 दिसंबर, 1941 के संकल्प के मामले में सिविल कोर्ट के पास सरकार के खिलाफ किसी भी दावे का निर्धारण करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। और मुकदमे को एस के तहत रोक दिया गया था।बॉम्बे राजस्व क्षेत्राधिकार अधिनियम, 1876 का 4। (1) आईएलऔर [1937] बॉम।464.

हम तदनुसार इस अपील की अनुमति देते हैं, 12 नवंबर 1952 के उच्च न्यायालय के फैसले और डिक्री को रद्द करते हैं, और 20 अप्रैल 1949 के विद्वान सिविल जज के फैसले को बहाल करते हैं। अपीलकर्ता वादी-प्रतिवादी से अपनी लागत का हकदार होगा।

अपील की अनुमति।

नोटः- यह अनुवाद और्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक **श्री आशीष मीना (न्यायिक अधिकारी)** द्वारा किया गया है

अस्वीकरणः-यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणित होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।